तिब्बत देश

तिब्बत पर भारत की शतुरमुर्गी नीति

3 नवंबर के दिन भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने अपने मंत्रियों और बड़े अफसरों के नाम एक फरमान जारी करके भारत सरकार को दुनिया भर में हंसी का पात्र बना दिया। इस फरमान में इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि वे नई दिल्ली के इंडियन हैबिटाट सैंटर में दलाई लामा के नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग न लें। नतीजा यह हुआ कि समारोह में आने का मन बना चुके मंत्रियों और संतरियों ने अपने–अपने बहाने बयान करके आयोजकों से माफी मांग ली। यहां तक कि समारोह की घोषित मुख्य अतिथि और अपनी राजनीतिक शालीनता और लोक व्यवहार के लिए पहचानी जाने वाली श्रीमती शीला दीक्षित को भी बहाना बनाकर समारोह से कन्नी काटनी पड़ी।

स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का एकमात्र उद्देश्य चीन सरकार को खुश करना था। इस फैसले का सदमे भरा पहलू यह था कि बरसों बाद ऐसा पहली बार हुआ कि भारत सरकार ने अपनी ही पहल पर इस तरह का कदम उठाया। इससे पहले ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे लगे कि चीन सरकार ने भारत सरकार से ऐसा कदम उठाने की कोई मांग की है। हां सारी दुनिया को पता था कि पिछले तीन–चार महीने के दौरान चीन सरकार की दलाई लामा के सवाल पर एक के बाद कम से कम छह मौकों पर बुरी तरह कूटनीतिक भद्द पिट चुकी है। इस दौरान चीन सरकार की हर तरह की धमकियों और हो–हल्ले के बावजूद आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रिया, जर्मनी और कनाडा के प्रधानमंत्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बांहें खोलकर और सरकारी तौर पर दलाई लामा का स्वागत किया। ऐसे में अपने मंत्रियों को दलाई लामा के स्वागत समारोह से बाहर रखकर भारत सरकार चीन सरकार का दिल किस हद तक जीत पाएगी यह तो समझना मुश्किल है, पर यह स्पष्ट है कि उसने ऐसा ओछा कदम उठाकर भारतीय कूटनीति के गिरे हुए स्तर को दुनिया भर के सामने नंगा कर दिया है।

इस समारोह का आयोजन तिब्बत समर्थक भारतीय सांसदों के सर्वदलीय मंच, गांधी शांति प्रतिष्ठान और भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों के केंद्रीय मंच कोर ग्रुप फार तिबेतन कॉज़ ने किया था। वे इस बात से उत्साहित थे कि दलाई लामा अमेरिकी संसद का ऐतिहासिक सम्मान 'कांग्रेशनल गोल्ड मैडल' पाने के बाद भारत लौट रहे थे। यह अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और इसका रुतबा भारत के 'भारत–रत्न' जैसा है। अमेरिका ने दो सौ साल में केवल 17 लोगों को दिया है। कूटनीतिक हलकों में इसे दलाई लामा को मिले शांति नोबेल पुरस्कार से कहीं ज्यादा राजनीतिक महत्व वाला माना जा रहा है। पिछले कई महीने से इस पुरस्कार पर चीनी हो–हल्ला और हताशा इसी बात को सिद्ध करते हैं।

17 अक्तूबर के दिन अमेरिकी संसद की ओर से राष्ट्रपति बुश ने दलाई लामा को यह सम्मान अपने हाथों से देकर दुनिया को यह संदेश भी भेजा कि दलाई लामा की हैसियत चीनी कब्जे में पिस रहे तिब्बत के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता से कहीं ऊपर एक विश्व नेता जैसी हो चुकी है। अमेरिकी संसद और अमेरिकी राष्ट्रपति की इस परोक्ष घोषणा पर चीन सरकार की तिलमिलाहट देखने लायक थी। उसने समारोह से पहले ही बीजिंग में अमेरिकी राजदूत को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज किया पर अमेरिकी संसद ने इस विरोध को दरकिनार कर दिया।

भारत और विदेश में होने वाली तिब्बत संबंधी गोष्ठियों में मुझसे अकसर यह सवाल पूछा जाता है कि भारत सरकार चीन सरकार के सामने तिब्बत के हितों का सवाल उठाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाती? इस सवाल पर हर बार विचार के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब भारत सरकार चीन के सामने कभी अपने देश के हितों के लिए मुंह खोलने का साहस नहीं दिखा पायी तो फिर भला किसी और देश के हित में बोलने के लिए वह कहां से हिम्मत लाएगी? स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने भी यही होता था कि चीन सरकार भारत के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर हर तरह का ज़हर उगलती रहती थी और भारत सरकार भारत–चीन रिश्तों की 'मिठास' और 'नज़दीकी' को बनाए रखने की एकतरफा जिम्मेदारी निभाने के नाम पर इस अपमान को चुपचाप पीकर अपनी महानता पर मोहित होती रहती थी।

नेहरू जी को पानी पी पीकर कोसने वाले भारतीय नेता तब देश को दिलासा देते नहीं थकते थे कि कांग्रेस राज खत्म होने पर चीन की दादागीरी के सामने भारत आत्मसम्मान के साथ खड़ा होगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन जाकर तिब्बत पर बचीखुची भारतीय संभावनाओं से चीन की गोद भराई की उसने भारतीय कूटनीति की आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। पिछले एक साल में एक के बाद एक घटने वाली तीन घटनाओं ने अब इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भारत भले ही आर्थिक, वैज्ञानिक या सैनिक तौर पर कितना ही मजबूत हो जाए लेकिन चीन के सामने दुम दबाकर सलाम करने की उसकी नियति अब एक शाश्वत सत्य बन चुकी है।

कुछ महीने पहले चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ भारत यात्रा पर आए थे। इस यात्रा से ठीक पहले दिल्ली में चीनी राजदूत ने जिस बेशर्मी के साथ भारत के अरुणांचल राज्य पर चीन का हक जताया और भारत सरकार ने उस पर जैसी आत्मसम्मान विहीनता का परिचय दिया उसने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि भारत–चीन रिश्तों में भारत की औकात क्या है। पिछले दिनों श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन यात्रा पर गए थे। उनके भारत लौटने के ठीक अगले ही दिन चीन सरकार ने जिस आक्रामक तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर चीनी अधिकार को दोहराया वह दिखा रहा था कि चीनी नेताओं के दिल में भारत के वरिष्ठ नेताओं के लिए क्या भावनाएं हैं। लेकिन इसके बाद भी भारतीय विदेश मंत्रालय के अफसर इस यात्रा को भारत–चीन रिश्तों में एक महान उपलब्धि की तरह पेश करते आ रहे हैं। यह सब देखकर नेहरू काल में चीन के प्रति भारत सरकार के अंधे और एकतरफा प्यार के माहौल में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन–लाई की वह टिप्पणी याद आती है जिसमें उन्होंने भारतीय नेताओं को अपने आप पर मोहित रहने वाले बेवकूफ कहा था।

आज हाल यह है कि चीन हर मोर्चे पर भारत के हितों के खिलाफ अभियान चला रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के रास्ते वह भारत की सैनिक घेरेबंदी कर रहा है; वह भारत के परमाणु कार्यक्रम की गति को तोड़ने में जुटा हुआ है; संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में भारत से मिले ऐतिहासिक समर्थन के बावजूद सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश को रोकने में लगा हुआ है और; जबरन कब्जाए हुए तिब्बत को भारत के खिलाफ सैनिक छावनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में लगता है कि चीन सरकार को किसी भी कीमत पर खुश करने को आमादा भारत सरकार न केवल नैतिकता और आत्मसम्मान की सीमाओं को तोड़ने में लगी हुई है बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को पहचानने की समझ भी खो चुकी है। उसे समझ में आना चाहिए कि तिब्बत पर चीन के कब्जे का बने रहना भारतीय हितों के लिए एक गंभीर और स्थायी खतरा है। अगर भारत के मेहमान दलाई लामा एक नए अंतर्राष्ट्रीय रुतबे और समर्थन के साथ उभर रहे हैं तो इससे कन्नी काटने के बजाए उनके साथ खड़े होने से भारतीय हितों को लाभ होगा। अगर भारत सरकार को दलाई लामा और तिब्बतियों का खुलकर साथ देने में डर लगता है तो उसे शालीनता पूर्वक तटस्थ बैठकर अनुकूल हालात का इंतजार करना चाहिए। शालीनता की सीमाओं से बाहर जाकर चीन को खुश करने से वह केवल चीनी उपनिवेशवाद के हाथ मजबूत करेगी। राष्ट्रीय आत्महत्या का इससे आसान रास्ता और नहीं होगा। — **विजय क्रान्ति**

अमेरिकी संसद में दलाई लामा और राष्ट्रपति बुश : युग पुरुष का सम्मान

दलाई लामा को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान से तिलमिलाया चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को दलाई लामा के साथ बातचीत का रुख अपनाने की सलाह दी

दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी ने दलाई लामा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। चीन के लिये यह कटे पर नमक के समान है। जर्मनी हो या आस्ट्रिया .. इस मामले में उसकी धमकी पर कोई भी देश ध्यान नहीं दे रहा।

वाशिंगटन, 17 अक्तूबर तिब्बत के निर्वासित शासक और सर्वोच्च धार्मिक गुरू परम पावन दलाई लामा को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान 'कांग्रेशनल गोल्ड मेडल' से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में इस पुरस्कार का दर्जा भारत में 'भारत–रत्न' जैसा है। अमेरिका ने यह कदम चीन के विरोध के बावजूद उठाया है और चीन में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यह पुरस्कार लेते हुए दलाई लामा ने फिर दोहराया कि वह बातचीत के रास्ते तिब्बत की समस्या हल करने के पक्ष में हैं।

समारोह का आयोजन अमेरिकी संसद के केंद्रीय कक्ष रोटुंडा में किया गया। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा अमेरिका के कई नामी गिरामी नागरिक भी उपस्थित थे। इस समारोह का बीबीसी और सीएनएन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी टीवी चैनेलों ने सीधा प्रसारण किया।

दलाई लामा को इससे पहले 50 से अधिक बार विभिन्न देशों में सम्मानित किया जा चुका है। इन पुरस्कारों में 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार और रेमन मेगसेसे पुरस्कार जैसे चोटी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी शामिल हैं। तिब्बत पर चीन के सैनिक कब्जे के खिलाफ तिब्बती जनक्रांति के असफल होने के बाद 1959 से वह भारत में रहे हैं।

अमेरिकी संसद की ओर से दलाई लामा को पुरस्कार देने की भूमिका स्वयं राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने निभाई। इस अवसर पर बुश ने चीन से अपील की कि वह तिब्बती नेता के साथ बातचीत का रुख अपनाये। उल्लेखनीय है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का अपने पर पर रहते हुए तिब्बती नेता दलाई लामा के साथ सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने का यह पहला कार्यक्रम था। इस मौके पर बुश ने कहा कि वह चीन के नेताओं से यह अपील करना जारी रखेंगे कि दलाई लामा का चीन में स्वागत किया जाये। अगर चीनी नेता ऐसा करते हैं तो वे पायेंगे कि यह भला आदमी शांतिदूत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका धर्म के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के प्रति आंखें मूंद कर नहीं रह सकता।

उन्होंने दलाई लामा की यह कहते हुए सराहना की कि उन्होंने तिब्बतियों की भावना को जिंदा रखा है। सम्मान ग्रहण करने के बाद दलाई लामा ने कहा, ''जहां तक तिब्बत के भविष्य का सवाल है, मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम आजादी नहीं बल्कि सिर्फ तिब्बत के लोगों के लिए चीनी गणराज्य के अंतर्गत अर्थपूर्ण स्वायत्तता चाहते हैं।''

अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने चीन की चेतावनी की अनदेखी करते हुए दलाई लामा का स्वागत किया था। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर दलाई लामा को सम्मानित किया जाता है तो इसका असर दोनों देशों के आपसी संबंधों पर पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका ने इन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे तिलमिलाये चीन ने बीजिंग में अमेरिकी राजदूत को तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियु जियांचाओ ने बीजिंग में पत्रकारों से कहा ''अमेरिका का यह कदम चीन के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। इससे चीन के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसका दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है।''

प्रवक्ता ने कहा कि ''हम नहीं चाहते कि कोई और हमें यह बताये कि हमें क्या करना है। तिब्बत हमारे भूभाग का अटूट हिस्सा है।'' चीन की तिलमिलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेश मंत्री यांग जियाची ने अमेरिकी राजदूत क्लार्क रेंडिट को तलब करके चीन का विरोध दर्ज कराया।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इस कदम से नाराज चीन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम मसले पर बर्लिन में होने वाली महाशक्तियों की बैठक में भाग नहीं लेने की घोषणा कर दी जिस कारण इस बैठक को सप्ताह भर के लिये टालना पड़ गया। वैसे

चीन ने इसका 'तकनीकी' कारण बताया।

समारोह से पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता डोना पेरिनो ने कहा था कि हम चीन को परेशान नहीं करना चाहते। चीन के साथ कई मुद्दों पर हमारे अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि चीन इस बारे में ज्यादा ही भावुक है।

चीन ने जर्मनी में दिसंबर में होने वाली जर्मन–चीन मानवाधिकार संवाद बैठक को भी अपनी ओर से रद्द कर दिया है। चीन पिछले महीने जर्मनी में तिब्बती नेता दलाई लामा और चांसलर एंजेला मर्केल की मुलाकात को लेकर भी बहुत नाराज है।

दलाई लामा ने राष्ट्रपति बुश से अपनी मुलाकात को पारिवारिक मिलन जैसा बताया। उन्होंने कहा कि बुश ने तिब्बत पर चिंता प्रकट करते हुए वहां की स्थिति के बारे में जानना चाहा। चीन की प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने हंसते हुए कहा, ''ऐसा तो हमेशा होगा।'' उन्होंने तिब्बत के प्रति चिंता जताने के लिए बुश का धन्यवाद ज्ञापित किया। दलाई लामा ने बुश दंपति के बारे में कहा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरा मानना है कि हमने काफी करीबी मित्रवत रिश्ते बनाये हैं।

दलाई लामा ने म्यामां में सैन्य प्रशासन द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की भी आलोचना की। उन्होंने इसकी तुलना तिब्बत में चीन के दमन से की।

खुशियां : दलाई लामा को यह अवार्ड दिए जाने पर अनेक प्रतिष्ठित लोगों तथा समाज के अनेक वर्गों में खुशी देखी गई। निर्वासित तिब्बती सरकार की राजधानी मैक्लोडगंज, धर्मशाला समेत भारत भर की तिब्बती बस्तियों में तिब्बत समुदाय के लोगों ने आतिशाबाजी की। निर्वासित तिब्बती सरकार के धार्मिक मामलों के मंच ने बयान जारी कर कहा है कि यह पहला मौका है जब अमेरिका ने उनके धर्मगुरू का स्वागत करते हुए उनके विचारों को विश्व स्तर पर सम्मान किया है। खुशी की बात है कि ऐसा चीनी दबाव के बावजूद किया गया है।

बुधवार रात को जब अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश के हाथों दलाई लामा को यह सम्मान दिया जा रहा था तो बीबीसी और सीएनएन समेत कई प्रमुख टीवी चैनेल इस समारोह का दुनिया भर मे प्रसारण कर रहे थे। धर्मशाला में इसे देखने के लिए तिब्बती समुदाय ने बड़े–बड़े टीवी स्क्रीन लगवाये थे।

निर्वासित सरकार के मुख्यालय धर्मशाला और तिब्बती बस्तियों में तो मानों दीपावली से पहले ही दीपावली मना ली गई।

क्या अर्थ है अमेरिकी पुरस्कार का ?

विश्व मंच पर दलाई लामा के नए रुतबे से चीनी उपनिवेशवाद का सिंहासन लड़खड़ा रहा है

– विजय क्रान्ति

दलाई लामा को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलने की घटना भारत सरकार और उसके सलाहकार भारतीय विश्लेषकों के लिए मानो रोज़मर्रा होने वाली हजारों घटनाओं में से एक थी। उनमें से किसी को शायद इतनी जानकारी भी नहीं थी कि अमेरिका में इस पुरस्कार का राजनीतिक रुतबा भारत में 'भारत–रत्न' के रुतबे के मुकाबले कई गुना बड़ा है। अमेरिका– चीन– तिब्बत मामलों के संदर्भ में भी इस सम्मान का राजनीतिक महत्व दलाई लामा को दिए गए 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी कहीं ज्यादा है। और पश्चिमी देशों और चीन के बीच चल रहे शीत युद्ध के संदर्भ में इस अमेरिकी फैसले का बहुत अहम महत्व है। आखिरकार अमेरिका में पिछले 200 साल में यह सम्मान केवल 17 लोगों को दिया गया है।

तिब्बत को हमेशा चीनी सरकार के आइने में से देखने को आदी हो चुके भारतीय नेताओं और भारतीय विश्लेशकों के पास यह पता लगाने की फुर्सत भी नहीं थी कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति दूसरे नंबर की महाशक्ति के घर में पांच साल में एक बार होने वाले राजनीतिक महाकुंभ (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पीपल्स कांग्रेस) के दौरान उसके सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा सम्मान देती है तो इसका क्या मतलब है? वे तो यह समझने को भी तैयार नहीं हैं कि सात समंदर पार हो रही इन घटनाओं का सीधा रिश्ता भारत की सीमा पर लगते उस इलाके से है जहां से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए पैदा हुए खतरे को वे खुद बहुत गंभीर मानते हैं।

दरअसल जो लोग चीन और तिब्बत के सवाल को महज तमाशबीनों वाले सतही नजरिए से देखते आए हैं उनकी नजर में 17 अक्तूबर के इस अमेरिकी पुरस्कार समारोह की औकात अमेरिका की ओर से चीन को चिढ़ाने के एक और शिगूफे से ज्यादा कुछ नहीं है। वे पूरी धार्मिक श्रद्धा के साथ यह मानकर बैठे हैं कि तिब्बत का सवाल अमेरिकी सरकार का सिर्फ एक मुहरा भर है जिसे वह चीन की सरकार को परेशान करने या उस पर व्यापारिक दबाव बनाने के लिए आए दिन चलती रहती है। ऐसा शायद इसलिए

परम पावन दलाई लामा ने जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल के साथ अपनी बैठक पर चीन की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा है कि चीन` ताकत की हेकड़ी` दिखा रहा है। 72 वर्षीय दलाई लामा ने चीन के गुस्से को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन इस तरह से तो जर्मनी के आंतरिक मामलों में ही दखल दे रहा है।

कैपिटल हिल के सामने पत्रकारों का अभिवादन करते हुए दलाई लामा : शांतिदूत

है कि ये लोग पिछले तीन दशक में तिब्बत के सवाल पर दुनिया भर में विकसित हो रहे तिब्बत समर्थक आंदोलन और दलाई लामा के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रभाव से पूरी तरह बेखबर हैं।

ऐसा नहीं कि अमेरिकी संसद को अचानक ही दलाई लामा के व्यक्तित्व में बड़प्पन दिखने लगा है। इससे पहले दलाई लामा को 17 देशों में 54 बार ऊंचे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें नोबेल शांति पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल हैं। लोकप्रियता के मामले में भी उनकी एक खास जगह बन चुकी है। दो महीने पहले जर्मनी की एक पत्रिका ने अपने सर्वेक्षण में पाया था कि जर्मन जनता में दलाई लामा जर्मन मूल के मौजूदा पोप और अपने राष्ट्रपति से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ठीक ऐसे ही परिणाम पिछले दिनों आस्ट्रिया में किए गए एक सर्वेक्षण में पाए गए। पश्चिमी देशों में जहां किसी सार्वजनिक मुद्दे पर एक हजार लोगों को इकट्ठा करना एक उपलब्धि माना जाता है, वहां दलाई लामा को सुनने के लिए ओलंपिक स्टेडियम भी खचाखच भर जाते हैं जो बड़े से बड़े रॉक स्टारों के लिए भी ईर्ष्या पैदा करने के लिए काफी है।

ऐसा नहीं कि अमेरिकी संसद को अचानक ही दलाई लामा के व्यक्तित्व में बड़प्पन दिखने लगा है। इससे पहले दलाई लामा को 17 देशों में 54 बार ऊंचे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें नोबेल शांति पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल हैं।

दलाई लामा के निरंतर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का अब यह हाल है कि विश्व भर के मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक संस्थाएं उन्हें अपने यहां आमंत्रित करती हैं। अमेरिकी कांग्रेस, यूरोपीय संसद, चेक गणराज्य जौर जर्मनी समेत कई देशों की संसदों में उनके सम्मान के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। पिछले तीस साल के दौरान विश्व भर की 20 से अधिक संसदें दलाई लामा और तिब्बत के समर्थन में 50 से अधिक प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। यह बात अलग है कि चीन सरकार के आगे बार–बार घुटने टेकने वाली भारत सरकार आज तक दलाई लामा को अपनी संसद में निमंत्रित करने का साहस नहीं जुटा पाई है।

तिब्बत के बारे में बदलते अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की झलक विश्व मंच पर फैलते तिब्बत समर्थक आंदोलन से मिलती है जो अब 50 से अधिक देशों में 150 से ज्यादा तिब्बत–समर्थक संगठनों के रूप में दिखाई देने लगा है। इन संगठनों का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि इन देशों की यात्रा पर जाने वाले चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को कई बार प्रदर्शनकारियों से डर कर अपने होटल के चोर दरवाजे इस्तेमाल करने पड़ते हैं।

इनमें से कई संगठनों के कार्यकर्ता तो चीन और तिब्बत के भीतर जाकर चीनी सुरक्षा व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए प्रदर्शन भी करने लगे हैं। 2005 जुलाई में तिब्बत रेल के उद्घाटन के समय बीजिंग रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश कार्यकर्ताओं ने तिब्बत समर्थक प्रदर्शन करके सरकार को हैरान कर दिया। इस साल जुलाई में अमेरिका में सक्रिय छात्र संगठन 'स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट' के चार विद्यार्थियों ने तिब्बत में एवरेस्ट बेस कैंप पर बीजिंग–ओलंपिक के खिलाफ लंबा प्रदर्शन किया। इंटरनेट पर इसके लाइव प्रसारण को दुनिया भर में कई टीवी स्टेशनों ने प्रसारित किया। इसी तरह 8 अगस्त के दिन जब चीन सरकार बीजिंग–ओलंपिक के साल का काउंट–डाउन मना रही थी ठीक उसी समय चीन की दीवार पर 40 फुट–40 फुट आकार का एक विशाल बैनर बीजिंग–ओलंपिक के विरोध में कई घंटे तक लहराता रहा। दुनिया भर में फैल रहे तिब्बत समर्थक आंदोलन का एक और पहलू यह है कि पिछले कई साल से यूरोप के एक हजार से ज्यादा शहरों की म्युनिस्पिल कमेटियां 10 मार्च के तिब्बत–जनक्रांति दिवस पर अपने सरकारी भवन पर तिब्बत का झंडा लहराती आ रही हैं। कुछ ने तो अपने शहरों में कुछ सड़कों के नाम बदलकर उन्हें तिब्बत समर्थक नाम दे दिए हैं। केवल इतना ही नहीं, चीन से बाहर लोकतांत्रिक आंदोलन चलाने वाले चीनी संगठनों ने भी कुछ साल से तिब्बत–समर्थक संगठनों के साथ संयुक्त प्रदर्शन करने और दलाई लामा के प्रति समर्थन जताने जैसे कदमों से चीन सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

उधर तिब्बत और चीन के भीतर भी चीन सरकार के दमन और कड़े कानूनों के बावजूद दलाई लामा का प्रभाव वैसा कम नहीं है जैसा चीन का प्रचारतंत्र दिखाने में लगा रहता है। दलाई लामा ने जब से

तिब्बत के लिए पूर्ण आजादी की जगह 'वास्तविक स्वायत्तता' का मध्य मार्ग अपनाया है तब से वह लगातार चीन सरकार से आग्रह करते आ रहे हैं कि उन्हें तिब्बत और चीन के कुछ बौद्ध तीर्थों की यात्रा की अनुमति दी जाए। इस पर दलाई लामा की लोकप्रियता जांचने के लिए चीन सरकार ने इस साल के शुरू में कुम्बुम कस्बे में एक अजीब खेल खेला। वहां चीनी तंत्र ने दलाई लामा के आने की अफवाह फैला दी जिससे पता चल सके कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन देखते–देखते जिस तरह से आसपास के चीनी प्रांतों और तिब्बती इलाकों से तिब्बती और चीनी श्रद्धालुओं का वहां जमाव शुरू हुआ उसने सरकार को चौकन्ना कर दिया। बाद में सेना बुलाकर कस्बा खाली कराने की नौबत आ गई।

इससे पहले बाघ और दूसरे जंगली जानवरों की रक्षा के लिए दलाई लामा की ओर से भारत के अमरावती में जारी अपील ने चीन सरकार की नाक में जो दम किया उसे भी बीजिंग के नेता नहीं भूल पाए हैं। दलाई लामा की अपील पर इस साल के शुरू में चीन के सिचुआन (तिब्बत का खम प्रांत) में तिब्बतियों ने बाघ, तेंदुए और दूसरे जानवरों की खाल के कपड़ों की होली जलाने का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने चीनी शासकों को दिखा दिया कि निर्वासन में बैठे दलाई लामा का असर कितना गहरा है। हर साल अगस्त में वहां के लिथांग में होने वाले घुड़दौड़ समारोह में इस बार इसी विवाद को लेकर भारी चीन विरोधी प्रदर्शन हुए जिनकी गूंज अभी तक जारी है।

पिछले 57 साल के जबरन कब्जे के बावजूद चीन तिब्बत में दलाई लामा में आस्था और आजादी की ललक को खत्म नहीं कर पाया। धार्मिक नेतृत्व में दखल करने के लिए बीजिंग ने 1990 वाले दशक में पहले तो करमा–पा के अवतार को गद्दी पर बिठाकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद पंचेन लामा के अवतार की खोज के दौरान असली अवतार को गिरफ्तार करके उसकी जगह अपने एक कठपुतली बालक को बिठा दिया। करमा–पा तो 2000 की नववर्ष रात्रि में भागकर भारत में दलाई लामा के पास आ गए। सरकारी पंचेन लामा का हाल यह है कि उसे आज तक तिब्बती जनता ने स्वीकार नहीं किया। आज हालत यह है कि 'तिब्बत आटोनामस रिजन' में दलाई लामा या पंचेन लामा का फोटो रखने पर सात साल की कैद की सजा है।

इधर पिछले कई साल से रेडियो और इंटरनेट ने दलाई लामा की पहुंच आम तिब्बतियों के एक बड़े वर्ग तक बना दी है। शीतयुद्ध के दिनों में पश्चिमी देशों से संचालित 'रेडियो फ्री यूरोप' की तर्ज पर चलने वाले रेडियो 'रेडियो फ्री एशिया', 'वॉयस आफ अमेरिका' और 'वॉयस आफ टिबेट' के माध्यम से तिब्बती जनता को वह सब जानकारी मिलने लगी है जिसे चीनी प्रशासन उससे छिपाता रहा है। इसने दलाई लामा के प्रति उसकी आस्था को नया बल दिया है। टूरिज्म के विकास और टेलिफोन तथा इंटरनेट के कारण अब तिब्बत और चीन के भीतरी हालात की असलियत को जानना बाहरी दुनिया के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं रहा। चीनी आर्थिक विकास की वजह से चीन में विकट आर्थिक विषमता, गले तक पहुंच चुके भ्रष्टाचार, गरीब जनता के शोषण और राजनीतिक दमन के कारण वहां जनता के मन में जो आक्रोश फूट रहा है उसकी जानकारी भी अब बाहर आने लगी है।

इसके अलावा चीन के भीतर तिब्बत जैसी समस्या से दो–चार हो रही अन्य कई 'राष्ट्रीयताओं' में भी जाग्रति आने लगी है। चीन में हान समेत इन राष्ट्रीयताओं को '56–बहनें' कहा जाता है। हान जाति के नरसंहारों और 'जनसंख्या इंजिनियरिंग' के कारण आज के चीन में बाकी राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या का अनुपात 10 प्रतिशत से भी कम रह गया है। हान अत्याचारों से पीड़ित इन 55 'बहनों ' को अब बाहरी दुनिया के संपर्क में आकर अपनी असली हालत समझ आने लगी है और चीन के पुराने उपनिवेशवादी पापों की कलई खुलने लगी है। सिंकियांग में तुर्की उइगुर मुस्लिमों तथा भीतरी मंगोलिया के मंगोलों में तो हान चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ हिंसक आवाज उठने से अब उस चीन सरकार ने भी 'आतंकवाद' के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है जो भारत और नेपाल में माओवादी, नक्सलवादी तथा उ.पूर्वी राज्यों के आतंककारी संगठनों को दशकों से पैसे, हथियार, ट्रेनिंग वैचारिक समर्थन देती आ रही है।

चीन सरकार को अब एक और संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। बीजिंग ओलंपिक के कारण लाखों नागरिकों को बेघर किए जाने तथा निर्माण कंपनियों और उत्पादन केंद्रों में ठेकेदार कंपनियों द्वारा लाखों चीनी ग्रामीणों को बंधुआ बनाकर जबरन मजदूरी कराने की घटनाओं के कारण पश्चिमी देशों में बीजिंग ओलंपिक की नैतिकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कई देशों में मानवाधिकार और दूसरे स्वयंसेवी संगठनों ने बीजिंग ओलंपिक के बायकॉट की मांग उठानी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर दलाई लामा चीनी उपनिवेशवाद से जूझते छोटे–छोटे देशों और लोकतंत्रवादियों की नई आशा बन कर उभरते हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।

भारतीय नेताओं और भारतीय विश्लेशकों के पास यह पता लगाने की फुर्सत भी नहीं थी कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति दूसरे नंबर की महाशक्ति के घर में पांच साल में एक बार होने वाले राजनीतिक महाकुंभ (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पीपल्स कांग्रेस) के दौरान उसके सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा सम्मान देती है तो इसका क्या मतलब है?

दलाई लामा एक सभा को संबोधित करते हुए : अहिंसा की ताकत

एक संत की वाणी का खुला और निर्मम दमन करता चीन

दलाई लामा को अमेरिकी सम्मान चीन को चेतावनी

'राष्ट्रीय सहारा' *और* ***'पंजाब केसरी'*** *के संपादकीय*

तिब्बत पर अपना अवैध कब्जा जमा लेने के करीब आधी सदी बीत जाने के बावजूद चीन उसे अपने एक स्वाभाविक और स्वस्थ हिस्से के रूप में न तो दुनिया के सामने पेश कर सका है और न ही दुनिया से वैसा मनवा सका है।

अमेरिका जब दलाई लामा को कांग्रेशनल गोल्ड मैडल के जरिये अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजता है तो इसके विरोध में चीन का गुस्सा कितना पोला और पिलपिला नजर आता है। वह चाहकर भी अगर अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो उसका कारण साफ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका इस समय विश्व की अकेली और ऐसी महाशक्ति है जिसको किसी भी हद तक जाकर दादागिरी करने से परहेज नहीं है और अपनी तमाम शक्ति–गाथाओं के बावजूद चीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि इसलिए भी कि तिब्बत पर अपना अवैध कब्जा जमा लेने के करीब आधी सदी बीत जाने के बावजूद चीन उसे अपने एक स्वाभाविक और स्वस्थ हिस्से के रूप में न तो दुनिया के सामने पेश कर सका है और न ही दुनिया से वैसा मनवा सका है।

आज से करीब छह दशक पहले जब पंडित नेहरू तिब्बत को चीन के हवाले करने का राजनीतिक और सांस्कृतिक अपराध कर आये थे, उस अपराधबोध से भारत ही जब आज तक नहीं उबर पाया है तो चीन, जिसे उस अपराध का सौ फीसदी फायदा मिला, उस अपराध बोध से भला कैसे उबर सकता है। वह नहीं उबर सका, इसका सबसे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए कि चीन द्वारा कब्जाए जाने के बाद दमन और धौंस पट्टी का शिकार बना दिए गये तिब्बत के निर्वासित, सैन्य शक्तिविहीन और महज आध्यात्मिक गुरू होने के बावजूद अकेले दलाई लामा चीन की पूरी ताकत और तानाशाही पर भारी पड़ते रहे हैं।

तिब्बती तो तिब्बती ही हैं, वे चीनियों की तरह हान नहीं हैं। इसलिए तो चीन ने करोड़ों हान तिब्बत में बसा कर वहां की आबादी में रची–बसी तिब्बती संस्कृति का चेहरा और संतुलन बिगाड़ कर रख देने की भरसक कोशिश कर ली है। पर इससे न तो वह तिब्बतियों द्वारा वहां चलाये जा रहे संघर्ष को खत्म कर पाया है, न ही दुनिया से तिब्बत नामक मुद्दे का वजन और चमक कम कर पाया है और न ही दलाई लामा के आध्यात्मिक बल से उपजी राजनीकि हस्ती को खरोंच लगा पाया है। चीनी नेताओं के मन में बसे डर की हालत तो यह है कि दलाई लामा कहते हैं, क्योंकि वे इससे अधिक दबाव बना पाने की हालत में नहीं है कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ चीन के भीतर रहते हुए अर्थपूर्ण स्वायत्ता चाहिए पर चीनी सत्ताधीशों के कान इतना तक सुनने को भी तैयार नहीं है।

दलाई लामा भरोसा दिलाते रहते हैं कि इस स्वायत्तता को वे आजादी की सीढी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे पर चीनी सत्ता केंद्रों में पसरा अपराध बोध ा एक संत की वाणी का खुला और निर्मम दमन उस दुनिया में हो रहा है जहां कहने को एक संयुक्त राष्ट्र है, लोकतंत्र का दम भरने वाले असंख्य देश हैं और मानव अधिकारों का नाम लेकर छत पर से चिल्लाने वाले ढ़ेरों संगठन मौजूद हैं। चिंता तो बस इतनी है कि तिब्बत की इस कुटिल दुनिया में तक कौन सुनेगा जब दलाई लामा भी नहीं रहेंगे। न जाने चीन कब कौन सा खेल खेल दे क्योंकि उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी अड़चन है, उसका नाम है दलाई लामा। (राष्ट्रीय सहारा, 20 अक्तूबर 2007)

दलाई लामा से खौफजदा क्यों है चीन

(**अश्विनी कुमार**, पंजाब केसरी, 20 अक्तूबर)

अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपति बुश ने भारत के मेहमान तिब्बत के धर्मगुरू दलाई लामा को सबसे बड़ा कांग्रेशनल स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। अमेरिका में इस पुरस्कार का रुतबा वही है जो भारत में भारत–रत्न का है। राष्ट्रपति बुश ने चीन के विरोध ा को दरकिनार करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लिया। चीन अमेरिकी संसद के इस फैसले का पहले ही विरोध ा कर चुका था और उसने ईरान के मसले पर अमरिका तथा दूसरे पश्चिमी देशों के साथ होने वाली शिखर वार्ता का बहिष्कार करने की घोषणा कर डाली और महाशक्तियों की इस बैठक को स्थगित करना

पड़ा था। दलाई लामा को स्वर्ण पदक भेंट किए जाने के बाद चीन सरकार के प्रवक्ता ने दलाई लामा को जमकर कोसा और बुश तथा सरकार की जमकर आलोचना की। यह तथ्य है कि इतने विरोध के चलते अमेरिकी कांग्रेस ने न सिर्फ दलाई लामा का कद बढ़ाया बल्कि विश्व को यह बता दिया कि शांति और अहिंसा की मशाल लेकर चलने वाले इस भिक्षु नेता से चीन सरकार कितना डरती है। शायद चीन सरकार को यह साफ दिखाई देने लगा है कि अमेरिकी संसद की इस घटना के चलते तिब्बत आंदोलन को और गति मिलेगी तथा अगले वर्ष बीजिंग ओलंपिक का अंतरराष्ट्रीय बायकाट भी हो सकता है। चीन भला कैसे भूल सकता है कि 1980 में मास्को ओलंपिक के अंतरराष्ट्रीय बायकाट के बाद कम्युनिस्ट सोवियत संघ का कैसा बुरा हाल हुआ था और उसकी कहानी दस साल के भीतर सोवियत संघ के बिखराव के साथ खत्म हुई थी? ताइवान भी चीन के लिए सिरदर्द बना हुआ है।

दलाई लामा के व्यक्तित्व ने चीन सरकार के मन में कितना खौफ पैदा किया हुआ है इसकी एक झलक पिछले एक दो महीने में दलाई लामा की आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी की यात्राओं के दौरान दुनिया को पहले ही मिल चुकी है। पहले तो बीजिंग सरकार ने सार्वजनिक तौर पर इन देशों की सरकारों को सलाह दी कि वे दलाई लामा को अपने देश में आने की अनुमति नहीं दें। वह इन सरकारों की इस दलील को भी सुनने को तैयार नहीं थी कि दलाई लामा सरकारी निमंत्रण पर नहीं बल्कि कुछ नागरिक संगठनों के बुलावे पर आ रहे हैं।

पहले तो आस्ट्रेलिया की सरकार घबरा गई और उसने आश्वासन तक दे डाला कि प्रधानमंत्री जान हावर्ड चीन की बात मानते हुए दलाई लामा से नहीं मिलेंगे लेकिन हावर्ड साहब को यह याद नहीं रहा कि उनकी असली जवाबदेही चीन को नहीं बल्कि अपने देश की जनता को है, जिसके वोट के बल पर वे राज कर रहे हैं। आखिरकार आस्ट्रेलिया में दलाई लामा के समर्थन में उठे आंदोलन के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री हेलेन क्लार्क तो उनसे भी दो कदम आगे निकल गईं। उन्होंने चीन सरकार की धमकियों की परवाह किये बिना आस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर ही दलाई लामा के साथ मुलाकात कर चीन सरकार को उसकी औकात दिखा दी। पिछले महीने जर्मनी की चांसलर श्रीमती एंजेला मर्केल ने तो चीन सरकार की धमकियों की बरसात के बीच दलाई लामा का सरकारी तौर पर खुल्लमखुल्ला स्वागत करके चीन सरकार को ठेंगा दिखा दिया। यह सब पहली बार नहीं हुआ। 2004 में दलाई लामा की यात्रा के दौरान कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी अपनी जनता के दबाव के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। तब विश्व बैंक को भी तिब्बत समर्थकों के दबाव के आगे झुकते हुए चीन को अरबों डारल के विकास ऋण पर फैसला रोकना पड़ा था। इन उदाहरणों से सबक लेते हुए कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री चीन सरकार के विरोध के बावजूद यह घोषणा कर चुके हैं कि अगले सप्ताह कनाडा की यात्रा पर आ रहे दलाई लामा से वह खुलकर मुलाकात करेंगे।

दलाई लामा : विश्व भर में सबसे ज्यादा सम्मानित युग पुरुष

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति बुश ने कहा कि अमेरिका धार्मिक तौर पर दमितों की दुर्दशाओं को नहीं देख सकता या मुहं नहीं मोड़ सकता और यही कारण है कि वह चीनी नेताओं से दलाई लामा का चीन में स्वागत करने का आग्रह जारी रखेंगे।

भारत ने दलाई लामा को शरण दी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के वक्त तिब्बती आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला लेकिन अब भारत ने अपनी तिब्बत नीति का परित्याग कर दिया है और सरकार खामोश होकर बैठ गई है। कैसी विडंबना है कि दलाई लामा के सम्मान में दुनिया भर की संसदें और नेता खड़े होकर ताली बजाते हैं। लेकिन इस भिक्षु को समर्थन देना तो दूर की बात है, उन्हें भारतीय संसद को संबोधित करने को आमंत्रित करने का साहस भी हमारी सरकारों में नहीं है। भारत सरकार और राजनेताओं को चाहिए कि वह राष्ट्रीय आत्मसम्मान दिखायें और तिब्बत आंदोलन को पुनः अपना नैतिक समर्थन दें।

कैसी विडंबना है कि दलाई लामा के सम्मान में दुनिया भर की संसदें और नेता खड़े होकर ताली बजाते हैं। उस भिक्षु को समर्थन देना तो दूर की बात है, उन्हें भारतीय संसद को संबोधित करने को आमंत्रित करने का साहस भी हमारी सरकारों में नहीं है।

यूथ फ्रंट के कार्यकर्ता चीनी माल की होली जलाते हुए : भारत की चिंता

चीनी सामान की होली जलाई गई

भारतीय अर्थव्यवस्था पर चीनी हमले के खिलाफ युवकों ने रोष जताया

फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने अपने वक्तव्य में भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद से अपील की कि वह इस बात को गंभीरता से ले कि सस्ते चीनी सामान के कारण भारत के खिलौना उद्योग, इलेक्ट्रोनिक उद्योग, पटाखा उद्योग और हथकरधा वस्त्र उद्योग गंभीर संकट में हैं।

इस साल गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर 'द यूथ लिबरेशन फ्रंट आफ तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान और मंगोलिया' ने नई दिल्ली में भारतीय संसद के सामने 'मेड इन चाइना' उपभोक्ता वस्तुओं की होली जलाकर एक नए आंदोलन का श्रीगणेश किया। फ्रंट के लगभग दो सौ कार्यकर्ताओं और उनके तिब्बती समर्थकों ने संसद मार्ग पर चीन में बने कपड़ों, खिलौनों और इलेक्ट्रोनिक सामग्री की यह होली जलाकर भारत के नीति निर्धारकों का ध्यान इस दुखद तथ्य की ओर खींचा कि सस्ते चीनी माल के कारण भारत के लाखों परिवारों के सामने जीने मरने का संकट पैदा हो चुका है।

फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र चौधरी ने अपने वक्तव्य में भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद से अपील की कि वह इस बात को गंभीरता से ले कि सस्ते चीनी सामान के कारण भारत के खिलौना उद्योग, इलेक्ट्रोनिक उद्योग, पटाखा उद्योग और हथकरधा वस्त्र उद्योग बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। चीन की आक्रामक बाजार नीति और भारत सरकार की उदासीनता के कारण पूरे भारत के बाजार 'मेड इन चायना' की बाढ़ से लकवाग्रस्त हुए पड़े हैं। श्री चौधरी ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसने समय रहते इस दिशा में गंभीर और प्रभावी कदम नहीं उठाए तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और चीन की कठपुतली बन जाएगी।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन की धमकियों का जवाब दिया

कहा दलाई लामा का सरकारी दफ्तर में स्वागत किया जाएगा

ओटावा, 18 सितंबर ऐसा लगता है कि दलाई लामा के सवाल पर दुनिया भर की सरकारों को धमकाने वाली चीन सरकार के सितारे इन दिनों खासी गर्दिश में हैं। दलाई लामा की यात्राओं को रोकने के नाम पर आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, आस्ट्रिया और जर्मन सरकारों के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद अब चीन सरकार को कनाडा सरकार से जोरदार शिकस्त मिलने जा रही है। बीजिंग से बार–बार आने वाली धमकियों की परवाह न करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री श्री स्टीफेन हारपर ने उसे बता दिया है कि अगले महीने दलाई कनाडा की प्रस्तावित यात्रा पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। बल्कि उन्होंने चीन के जले पर नमक छिड़कते हुए घोषणा की है कि वह दलाई लामा का सरकार के फेडरल कार्यालय में खुद स्वागत करेंगे।

इससे पहले चीन सरकार के प्रवक्ता ने कनाडा सरकार से दलाई लामा की यात्रा पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए कहा था कि हम दलाई लामा को किसी देश द्वारा अपने यहां रुकने की जगह देने या सरकारी स्तर पर के नेताओं से मुलाकात का विरोध करते हैं। चीन का आरोप है कि दलाई लामा एक 'पृथकतावादी' हैं जो चीन को तोड़ने पर आमादा हैं।

2004 में चीन सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पॉल मार्टिन को धमकियां देकर दलाई लामा से मिलने से रोक दिया था। लेकिन जन संगठनों और मीडिया के भारी दबाव के आगे झुकते हुए श्री मार्टिन को दलाई लामा से मिलना पड़ा था। यह मुलाकात गैरसरकारी थी और केवल पांच मिनट लंबी रही थी।

श्री हारपर ने अपनी घोषणा करते हुए बताया कि उन्हें दलाई लामा ने अपनी 2004 की कनाडा यात्रा के दौरान जो स्कार्फ भेंट किया था उसे उन्होंने आज तक संजो कर रखा हुआ है।

कनाडा के प्रधानमंत्री की इस घोषणा और चीन के रवैये को देखते हुए कनाडा के समाचार पत्रों ने आशंका व्यक्त की है कि इससे कनाडा और चीन के संबंधों में तनाव पैदा होगा। ये संबंध चीन के खराब मानवाधिकार रिकार्ड के कारण पहले ही खराब चल रहे हैं। श्री हारपर की इस घोषणा के बाद उनकी लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है।

♦ आंखों देखी

चेन्नई में रांग्ज़ेन बास्केटबाल टूर्नामेंट के आयोजन का यह चौथा साल था। दक्षिणी भारत में तिब्बती कालेज विद्यार्थियों की स्नेहमयी आंटी आशा द्वारा 2004 में शुरू किए गए और चेन्नई की टिबेटन स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मद्रास (त्सैम) द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में इस साल बंगलोर, वडोदरा, मैसूर, त्रिची, ऊटी और चेन्नई की 12 टीमों ने भाग लिया जिनमें से 3 लड़कियों की टीमें थीं।

21 सितंबर से ज. जयललिता इंडोर बास्केटबाल स्टेडियम में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में रांग्ज़ेन ट्राफी की पिछले साल की विजेता ऊटी ने इस साल भी बाजी मारी। लड़कों में दूसरा स्थान बंगलोर का रहा। लड़कियों में प्रथम स्थान बंगलोर और दूसरा चेन्नई का रहा। आशा जी के अनुसार इस टूर्नामेंट के आयोजन का लक्ष्य दक्षिणी भारत के तिब्बती कालेज विद्यार्थियों में एकता और आपसी संपर्क बनाना है।

खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और तिब्बती संघर्ष के प्रति समर्थन देने के लिए पहले दिन दो स्थानीय लोकप्रिय उद्यमी श्री राहुल जैन और सुश्री पूनम लालचंद मुख्य अतिथि थे। 23 दिन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि चेन्नई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल श्री वाल्टर दावाराम, पूर्व भारतीय हाकी कप्तान श्री वी भास्करन और लोकप्रिय तमिल फिल्म अभिनेत्री सुश्री स्वर्णमाल्या थीं। समापन समारोह में सुश्री अंजना रेड्डी ने तिब्बत की स्थिति पर दिल को छू लेने वाला विवरण पेश किया। त्सैम सदस्यों के प्रभावशाली तिब्बती सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबकी वाहवाही लूटी।

आशा आंटी ने टूर्नामेंट में प्रथम आने वाली लड़कों और लड़कियों की टीमों को 5000 रु, रनर अप टीमों को 3000 रु और सर्वोत्तम खिलाड़ी को 1000 रु के पुरस्कार दिए।

– लोबसांग जिग्मे की रिपोर्ट पर आधारित

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के अंग्रेज़ी विभाग ने 8 अक्तूबर को तिब्बत पर एक सेमिनार किया। प्रो. शिवाजी सरकार की अध्यक्षता वाले अंग्रेजी विभाग की पहल पर आयोजित इस सेमिनार में इंस्टीट्यूट के चारों विभागाध्यक्षों और 50 विद्यार्थियों के अलावा दलाई लामा के प्रतिनिधि और मंत्री श्री तेंपा सेरिंग और तिब्बती संसद के सभापति श्री पेंपा सेरिंग ने भी भाग लिया। तिब्बत की मानवाधिकार स्थिति, चीनी जनसंख्या को वहां बसाने के खतरे और निर्वासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। उपस्थित विद्यार्थियों ने तिब्बत की वर्तमान स्थिति और भारत–चीन संबंधों आदि के बारे में मुख्य वक्ताओं से कई सवाल किए।

नेपाल में तिब्बती विद्यार्थियों ने इस साल की परीक्षाओं में बहुत अच्छे परिणाम दिखाए। इस बार अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए काठमांडो में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया जिसमें सुश्री दोल्मा त्सोमो ने ऐसे बच्चों का पुरस्कार बांटे।

नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों के लिए चलाए जाने वाले स्कूलों में शिक्षा का अच्छा स्तर होने का एक परिणाम यह हुआ है कि चीनी कब्जे वाले तिब्बत में रहने वाले सैंकड़ों परिवार हर साल कानूनी या गैरकानूनी हर संभव रास्ता अपनाते हुए अपने बच्चों को चीनी स्कूलों के बजाए नेपाल और भारत भेजते हैं। इसका मुख्य कारण अपने बच्चों को चीनी स्कूलों में तिब्बत विरोधी शिक्षा और चीनी दुष्प्रचार से बचाना है।

फ्रंट ने चीन में बने कपड़ों, खिलौनों और इलेक्ट्रानिक सामग्री की यह होली जलाकर भारतीय नीति निर्धारकों का ध्यान इस ओर ... कि ... भारत ... लाखों परिवारों के ... मने जीने मरने का संकट पैदा कर चुका है

जर्मन प्रधानमंत्री एंजेला मेर्केल दलाई लामा की आगवानी करते हुए : नैतिक साहस

जर्मन प्रधानमंत्री ने चीनी गीदड़ भभकियों का करारा जवाब दिया

चीनी धमकियों के बावजूद दलाई लामा का स्वागत

चीन सरकार के विरोध और लगातार धमकियों के बीच जर्मन चांसलर सुश्री एंजेला मेर्केल ने ऐतिहासिक साहस दिखाया और प्रधानमंत्री की हैसियत से दलाई लामा से मुलाकात की। इस पर तिलमिलाई चीनी सरकार ने जर्मन सरकार से साथ चल रही वार्ताओं को स्थगित कर दिया।

बर्लिन, 23 सितंबर चीन सरकार के भारी विरोध और लगातार धमकियों के बीच जर्मन चांसलर सुश्री एंजेला मेर्केल ने ऐतिहासिक साहस दिखाया और प्रधानमंत्री की हैसियत से दलाई लामा से मुलाकात की। इस पर तिलमिलाई चीनी सरकार ने जर्मन सरकार से साथ चल रही वार्ताओं को स्थगित कर दिया, चीनी मीडिया में मेर्केल के खिलाफ दुष्प्रचार को हवा दी और जर्मन–चीन आर्थिक संबंधों के बिगड़ने की धमकियां जारी कीं।

यह पहला अवसर है जब किसी जर्मन चांसलर ने चीन सरकार की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे बताया कि जर्मन सरकार और जनता को अधिकार है कि वह अपने देश में किस मेहमान का स्वागत किस तरह से करे। सुश्री मेर्केल कुछ दिन पहले ही चीन की यात्रा पर गई थीं जहां उन्हें चीन सरकार के नेताओं ने दलाई लामा को अपने देश में घुसने से रोकने को कहा था और उरनसे मिलने के खिलाफ चेतावनी दी थी। सुश्री मेर्केल ने अपने देश में अपने उन अधिकारियों और विशेषज्ञों को भी चुप करा दिया था जो इस बात से डरे हुए थे कि चांसलर के इस कदम से चीन के साथ जर्मन आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा।

दलाई लामा–मेर्केल मुलाकात से ठीक पहले इसे कैंसिल करने की चीनी मांग के जवाब में जर्मन प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कर दिया कि निमंत्रण कायम रहेगा और दोनों की मीटिंग होकर रहेगी क्योंकि चांसलर ने सोच समझ कर उन्हें निमंत्रण दिया है।

इस मुलाकात के बाद बीजिंग में चीन सरकार के प्रवक्ता ने धमकी भरी जुबान में कहा कि, ''यह न केवल चीन के भीतरी मामलों में खुल्लमखुल्ला दखलंदाजी है बल्कि इससे चीन–जर्मन संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा और चीनी जनता की भावनाओं पर आधात होगा।'' चीन सरकार ने जर्मन सरकार से मांग की कि इस मुलाकात के कारण चीन–जर्मन संबंधों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी कदम उठाए। दूसरी ओर चीन सरकार के अंगूठे के नीचे चलने वाले इंटरनेट पर चीनी लोगों ने सुश्री मेर्केल के लिए 'चुड़ैल' जैसे घटिया शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया।

लेकिन इस मुलाकात ने जर्मनी में चांसलर मेर्केल की लोकप्रियता और और ऊंचा उठा दिया। यहां तक कि विपक्ष की ग्रीन नेता क्लाडिया रोथ ने चांसलर मेर्केल के व्यवहार को 'जिम्मेदाराना' बताते हुए कहा कि तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति का जर्मन हितों से सीधा संबंध है। सुश्री रोथ पिछली रैड–ग्रीन सरकार में मानवाधिकार कमिश्नर रह चुकी हैं। इसी तरह हैस्से प्रांत के प्रधानमंत्री रोलांड कोख़ ने कहा कि वह इस बात से बहुत खुश हैं कि मेर्केल ने दलाई लामा के मामले में चीन के आगे हथियार नहीं डाले।

ताकत का घमंड दिखा रहा है चीन : दलाई लामा

बर्लिन, 24 सितंबर परम पावन दलाई लामा ने जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल के साथ अपनी मुलाकात पर चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि चीन 'ताकत की हेकड़ी' दिखा रहा है। एक स्थानीय समाचार पत्र को दिये गये साक्षात्कार में दलाई लामा ने चीन के गुस्से को बेतुका बताया है।

उन्होंने कहा, ''चीन का यह रुख ताकत की हेकड़ी है। चांसलर मेर्केल से मुझसे नहीं मिलने की मांग करके चीन सरकार जर्मनी के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रही है।'' किसी पदासीन जर्मन चांसलर के साथ दलाई लामा की यह पहली बैठक थी। लेकिन दलाई लामा को जर्मनी की संसद और कई नगरों के सार्वजनिक समारोहों में दर्जनों बार आमंत्रित किया जा चुका है।

दलाई ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मेर्केल के साथ उनकी बैठक से चीन–जर्मनी के रिश्तों पर लंबे समय तक कोई असर पड़ेगा। उन्होंने इस बैठक को उत्साहजनक बताया।

कनाडा पहुंचने पर दलाई लामा का स्वागत : बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय रुतबा

आस्ट्रिया के चांसलर ने दलाई लामा से मुलाकात की

आस्ट्रिया में सबसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय नेता हैं दलाई लामा : सर्वेक्षण रिपोर्ट

वियना, 19 सितंबर चीन सरकार के कड़े विरोध के बावजूद आस्ट्रिया के चांसलर श्री अल्फ्रेड गुज़ेनबाउर ने आज दलाई लामा से मुलाकात की। सुबह सवेरे हुई इस मुलाकात का आयोजन चांसलर के सरकारी कार्यालय में किया गया।

आस्ट्रिया सरकार के प्रवक्ता स्वेन पुसवाल्ड ने बताया कि दोनों नेताओं की यह बैठक लगभग 45 मिनट चली। आस्ट्रिया के मीडिया ने इससे पहले चीनी दूतावास द्वारा इस बैठक के विरोध के समाचार प्रकाशित किए थे। चीन दलाई लामा की यात्राओं को लेकर पहले भी इस तरह का रुख अपनाता रहता है। बैठक के बाद अपने एक प्रसारित बयान में चांसलर ने कहा कि आस्ट्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। उन्होंने चीन सरकार के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दलाई लामा के साथ उनकी बातचीत का आस्ट्रिया–चीन संबंधों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।

आस्ट्रियन चांसलर की दलाई लामा के साथ मुलाकात को यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि चीन के कड़े शोर शराबे भरे विरोध के बीच जर्मनी की चांसलर सुश्री एंजेला मेर्केल भी चार दिन बाद बर्लिन में दलाई लामा के साथ मुलाकात करने वाली थीं।

दलाई लामा सबसे अधिक लोकप्रिय

इससे पहले 28 अगस्त के दिन एक सर्वेक्षण एजेंसी ने आस्ट्रिया के लोगों के बीच किए गए अपने सर्वेक्षण में पाया कि दुनिया के नौ वरिष्ठ राजनेताओं तथा हस्तियों की सूची में से सबसे अधिक लोकप्रिया नेता परम पावन दलाई लामा हैं। 62 प्रतिशत लोगों ने उन्हें अपनी पसंद का नेता बताया। उनके बाद जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल को 61 प्रश मतों के साथ दूसरा, आस्ट्रिया में जन्मे और आजकल कैलिफोर्निया के गर्वनर आर्नोल्ड श्वार्त्सनेगर को 60 प्रश तथा पोप बेंडिक्ट सोलहवें को 59 प्रश के साथ क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान मिला।

एपीए से जारी ओजीएम द्वारा कराये गये इस सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश में बहुत ही कम आस्ट्रियाई लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। लोकप्रियता की सूची में बुश की ही तरह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की–मून और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष श्री जोसे मानुएल बाराओ बार्रोसो को लोगों ने अपनी वरीयता में सबसे नीचे रखा। सर्वेक्षण में शामिल होने वाले 84 प्रतिशत लोगों ने बुश के प्रति अविश्वास व्यक्त किया। इस सर्वेक्षण के तहत आस्ट्रिया के 500 वयस्कों से टेलीफोन से साक्षात्कार किया गया।

सर्वेक्षण आंकड़े

आप इन लोगों पर विश्वास या अविश्वास करते हैं? (प्रतिक्रिया प्रश में)

	विश्वास	अविश्वास
दलाई लामा	62	13
एंजेला मेर्केल	61	26
श्वार्सनेगर	60	26
पोप बेनेडिक्ट	59	26
बिल गेट्स	43	29
जोस बरासो	22	29
बेन की मून	16	05
व्लादीमीर पुतिन	13	73
जार्ज डब्ल्यू बुश	06	84

स्रोत : ओजीएम/एपीए

इससे पहले जर्मनी में किए गए ऐसे ही एक सर्वेक्षण में भी दलाई लामा को सबसे अधिक लोकप्रिया पाया गया था। सामाजिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में निरंतर चलने वाली अशांति और अविश्वास के वातावरण में दलाई लामा जैसे व्यक्ति का लोकप्रिय होना एक शुभ संकेत है। यह लोंगों के मन में शांति की चाहत दिखाता है।

इससे पहले जर्मनी में किए गए ऐसे ही एक सर्वेक्षण में भी दलाई लामा को सबसे ज्यादा लोकप्रिया पाया गया था। सामाजिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अशांति और अविश्वास के वातावरण में यह लोंगों के मन में शांति की चाहत दिखाता है।

बीजिंग ओलंपिक में तिब्बत की भागीदारी की मांग : उपनिवेशवाद को चुनौती

तो अब ताइवान से होकर नहीं गुजरेगी बीजिंग ओलंपिक की मशाल

नहीं हो पाया चीन और ताइवान में समझौता

ताइवान का कहना है कि चीन इस मशाल की यात्रा का पहला पड़ाव ताइपे बनाकर यह जताना चाहता है कि जैसे ताइवान उसका ही एक हिस्सा है। गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानता है।

21 सितंबर अगले साल बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों की मशाल ताइवान से होकर नहीं गुजरेगी। चीन के साथ समझौता नहीं हो पाने के कारण ताइवान ने यह फैसला किया है। स्विटजरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की प्रवक्ता इमेनुएल मोरेउ ने गुरुवार को सेंट्रल न्यूज एजेंसी से कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद न सुलझ पाने के कारण मशाल अब चीनी ताइपे से होकर नहीं गुजरेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि आईओसी की इच्छा है कि चीनी ताइपे भी इस आयोजन में हिस्सा ले लेकिन चीन और ताइवान के बीच इस संबंध में कोई आपसी समझौता नहीं हो पाने के कारण यह संभव नजर नहीं आ रहा। अप्रेल 2007 में चीन ने मशाल के लिए मार्ग की योजना सार्वजनिक की थी जिसके तहत मशाल के राजधानी बीजिंग पहुंचने से पहले वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी से ताइपे होकर हांगकांग, मकाउ तथा कुछ और चीनी शहरों से गुजरने की योजना थी। लेकिन ताइवान ने अप्रैल में चीन की इस योजना को नामंजूर कर दिया।

ताइवान का कहना है कि चीन इस मशाल की यात्रा का पहला पड़ाव ताइपे बनाकर यह जताना चाहता है कि जैसे ताइवान उसका ही एक हिस्सा है। गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानता है जबकि ताइवान स्वंय को स्वतंत्र देश कहता है। मशाल के मार्ग के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों में बातचीत हुई थी।

बताया जाता है कि ताइवान अगस्त 2007 में मशाल को अपने यहां से गुजरने देने पर सहमत हो गया था लेकिन बाद में चीन की एक शर्त के कारण बात बिगड़ गई जिसमें कहा गया था कि मशाल के ताइवान से गुजरने के दौरान न तो ताइवान राष्ट्रीय झंडा प्रदर्शित किया जाए और न ही कोई ताइवानी प्रतीक ही दर्शाए जाएं।

ओलंपिक पर प्रदूषण का खतरा

आईओसी के अध्यक्ष जैक्स रोगे ने कहा है कि चीन में होने वाले ओलंपिक खेलों की कई स्पर्धाओं को प्रदूषण की वजह से स्थगित करना पड़ सकता है।

रोगे ने कहा है कि कम अवधि की स्पर्धाओं में प्रदूषण की वजह से कोई खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन प्रदूषण के कारण साइकिल रेस जैसी स्पर्धाओं को स्थगित करना पड़ सकता है। चीन ने प्रदूषण को कम करने कई प्रयास किए हैं और इस दिशा में बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है।

चीन में लगातार जारी निर्माण कार्य तथा कारों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी से वातावरण और प्रदूषित हुआ है। इसके अलावा चीन में ट्रेफिक जाम भी आईओसी की चिंता की बड़ी वजह है। बीबीसी के चीन में मौजूद संवाददाता का कहना है कि ओलंपिक के आयोजन को लेकर वहां मानवाधिकारों पर चर्चा गर्म हो रही थी लेकिन अब प्रदूषण भी बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है।

चीनी ओलंपिक साइकिल रेस स्पर्धा के निदेशक वांग जुनयान ने कहा कि रोगे का उक्त बयान हमें याद दिलाता है कि अभी पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जान कोट्स पहले ही कह चुके हैं कि उनके खिलाड़ी अगले साल इन खेलों के शुरू होने से ठीक पहले ही चीन पहुंचेंगे जिससे वे सांस लेने संबंधी समस्याओं से बचे रह सकें। चीन में ओलंपिक खेलों के शुरू होने में बस एक ही साल बचा है और इसकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

विवाद पर विवाद : चीन में ओलंपिक खेलों के आयोजन पर नित नये विवाद जुड़ते जा रहे हैं। मानवाधिकार, पत्रकारों को स्वतंत्रता, आयोजन संबंधी निर्माण कार्यों में लगे तिब्बती नागरिकों को भुगतान न होना तथा अब प्रदूषण। कुछ अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने चीन पर आरोप लगाया है कि ओलंपिक खेलों की तैयारियों में लगे मजदूरों का शोषण किया

♦ ओलंपिक

जा रहा है। इन आरोपों में कहा गया है कि चीन में बच्चे भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। चीन ओलंपिक की तैयारियों में जुटा है और इस कोशिश में वहां बड़े पैमाने पर निर्माण तथा अन्य गतिविधियां चल रही हैं। आरोप है कि मजदूरों से 15–15 घंटे काम लिया जा रहा है तथा उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं दी जा रही।

तिब्बत श्रमिकों को मजदूरी नहीं : ओलंपिक परियोजनाओं के लिये काम करने वाले तिब्बतियों के वेतन का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप भी चीन पर लगा है। कहा जा रहा है कि ओलंपिक परियोजनाओं के मद्देनजर अच्छे वेतन की उम्मीद में बीजिंग पहुंचे तिब्बतियों को वेतन तक नहीं दिया गया और वे किसी तरह बच बचाकर अपने घरों को लौट आये। मुक्त तिब्बत अभियान (फ्री टिबेट कैंपेन :एफटीसी) के अनुसार अनेक ऐसे तिब्बतियों से बातचीत की गई जो बेहतर मजदूरी की उम्मीद में बीजिंग गये थे लेकिन वहां की बंधुआ हालत के कारण बिना वेतन लिए वहां से भाग आए।

संगठन के अनुसार इस साल अप्रैल में आम्दो (चीनी : गांसू प्रांत) से सैकड़ों की संख्या में बीजिंग गये थे जहां उन्हें चीनी ठेकेदारों के एजेंटों ने बहुत अच्छा वेतन दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन वहां जाकर उनसे निर्माण स्थलों पर काम तो बहुत लिया गया पर भुगतान नहीं किया गया। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बीजिंग के निर्माण स्थलों पर हालत बंधुआ मजदूरी जैसी है। तिब्बत में ठेकेदारों के स्थानीय अधिकारियों ने वादा किया था कि बीजिंग में काम करने वाले हर तिब्बती को 1000 युआन (लगभग 7000 रु) प्रति माह का भुगतान किया जायेगा लेकिन उन्हें बीजिंग काम लेने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। कुछ लोगों को केवल 100–200 युआन प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया गया। जब इन लोगों ने अधिकारियों को पूर्व में किये गये वादों की ओर ध्यान दिलाया तो उनका कहना था, ''ओलंपिक के दौरान आपको अच्छा भुगतान किया जायेगा। उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जायेगी। लेकिन तब तक कठोर मेहनत करनी होगी।''

वापस लौटे तिब्बती भागकर आये हैं क्योंकि वे जानते थे कि अधिकारी उन्हें आराम से वापस नहीं जाने देंगे। लौटने वाले मजदूरों ने बताया कि बीजिंग पहुंचने के बाद इन लोगों को मिलटरी ड्रिल में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा उन्हें स्टेडियम गार्ड, टुअर गाइड तथा होटल तथा रेस्त्रां में काम का प्रशिक्षण भी दिया गया।

एफटीसी के मैट विटीकेस ने उक्त घटनाओं के बारे में कहा, ''यह तथा अन्य मानवाधिकार उल्लंघन चीन में ओलंपिक की तैयारियों के दौरान हो रहे हैं। इस पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की चुप्पी अपराध के समान है।''

पत्रकारों के अधिकारों का हनन : तमाम तरह के दबाव और अपीलों के बावजूद चीन में पत्रकारों के अधिकारों का हनन जारी है। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को मानवाधिकार संबंधी रिकार्ड सुधारने और मीडिया स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के आश्वासन के बावजूद चीन पत्रकारों के अधिकारों का लगातार हनन कर रहा है।

इस मानवाधिकार निगरानी एजेंसी का कहना है कि चीन में पत्रकार पुलिस के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के लगातार शिकार हो रहे हैं। पत्रकार सादे कपड़े वाले उन गुंडों का शिकार हो रहे हैं जो देखने में सरकारी नौकर जैसे लगते हैं लेकिन उनके कहीं आने जाने और सूचना के लिए लोगों से मिलने पर दादागीरी से पेश आते हैं। संगठन की सोफी रिचर्डसन के अनुसार ऐसा लगता है कि स्वतंत्र मीडिया चीन सरकार को दुश्मन नजर आता है।

बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर चीन सरकार ने आईओसी को आश्वासन दिया था कि इस आयोजन के दौरान वह मीडिया पर प्रतिबंधों को कम करेगी। चीन ने यह आश्वासन ओलंपिक चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुपालन में दिया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाले देशों को इस अनुच्छेद का अनुपालन करना होता है।

आईओसी ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगता हो कि चीन में मीडिया को स्वतंत्रता दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि चीन में हाल ही में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि वहां मीडिया पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध जारी हैं।

इस बीच तिब्बत आंदोलन के संयोजक संगठन आईटीएसएन ने बीजिंग ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार की है। संगठन का कहना है कि बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह पर दुनिया भर की निगाहें चीन पर होंगी और यह हमारे लिये विश्व के समक्ष तिब्बत की वास्तविक स्थिति को रखने का सुनहरा तथा अनूठा मौका है। उन्होंने कहा कि तिब्बत आंदोलन अगस्त 2008 तक के समय को उपनिवेश बनाए गए तिब्बत की वास्तविकताओं को शेष दुनिया के समक्ष रखने तथा चीनी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिये करेगा।

चीनी ठेकेदारों के एजेंटों ने बहुत अच्छा वेतन दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन वहां जाकर उनसे निर्माण स्थलों पर काम तो बहुत लिया गया पर भुगतान नहीं किया गया। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बीजिंग के निर्माण स्थलों पर हालत बंधुआ मजदूरी जैसी है।

एक सभा में भाषण देते हुए शेन शुई–बियान : राष्ट्रीय आत्मसम्मान

ताइवान ने निर्वासित तिब्बती सरकार से हाथ मिलाने का आह्वान किया

ताईवानी राष्ट्रपति ने दलाई लामा को चीनी चुनौती से मिलकर निबटने का न्यौता दिया

ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि आज तिब्बत और ताइवान की एक जैसी ही स्थिति है और दोनों के समक्ष चीन का खतरा है। ताइवानी तिब्बतियों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, वे तिब्बत की लड़ाई में उनका समर्थन करते हैं। '

ताइपे ताइवान के राष्ट्रपति शेन शुई –बियान ने निवार्सित तिब्बती सरकार से चीन को चुनौती देने में ताइवान से हाथ मिलाने का आह्वान किया है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा को ताइवान की यात्रा पर आने का भी न्यौता दिया है।

'तिब्बत में मानवाधिकार' विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शेन ने कहा कि तिब्बत, चीन की सत्ता को नकारने वाली तथा चीन के सैन्य दमन से आजादी चाहने वाली कमजोर शक्तियों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके अलावा यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिये भी परीक्षा के समान है कि वह मानवाधिकार मामलों के प्रति क्या रुख अपनाता है।

इस संगोष्ठी में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, भारत, मेक्सिको, स्वीडन, नार्वे तथा जापान के अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। दो दिन की इस संगोष्ठी में विदेशों में रहने वाले लोकतंत्र समर्थक चीनी कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

राष्ट्रपति शेन ने कहा, ''आज तिब्बत और ताइवान की एक जैसी ही स्थिति है और हम दोनों के समक्ष चीन का खतरा है। इसलिए ताइवान के लोग तिब्बतियों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। वे तिब्बत की लड़ाई में उनका समर्थन करते हैं।'' उन्होंने कहा,''हम तिब्बत के भविष्य के बारे में दलाई लामा के फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ताइवान और तिब्बत एक दूसरे का बेहतर सहयोग कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि निर्वासित तिब्बती सरकार और ताइवान के बीच संबंधों और सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए दलाई लामा ताइवान की यात्रा कर सकते हैं।'' राष्ट्रपति बियान ने कहा कि चीन की योजना अगले साल के ओलंपिक खेलों को देश की मानवा धिकार हनन गतिविधियों को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडे के रूप में इस्तेमाल करने की है।''

उन्होंने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो यह ओलंपिक की भावना तथा चार्टर का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि चीन मीडिया को वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने और उसके बारे में दुनिया को बताने से रोक रहा है।

उन्होंने कहा कि ताइवान और तिब्बत की समस्या एक जैसी है क्योंकि उनकी स्वायत्तता को चीन ने खतरे में डाल दिया है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी तरह दलाई लामा भी मानते हैं कि ताइवान के भविष्य का फैसला ताइवान की जनता को ही करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि ताइवान और चीन 1949 में अलग हो गये थे। ताइवान को चीन अपने से अलग हुआ एक प्रांत मानता है जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु देश कहता है जिसे 24 देशों ने मान्यता दी है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत और ताइवान पर समान रूप से ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''ताइवान की मानवाधिकार स्थिति पर भी अधिक न सही लेकिन उतना ही ध्यान दिए जाने की जरूरत है जितना अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत पर देता है।''

चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर 988 बैलेस्टिक मिसाइलों की तैनाती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2.3 करोड़ लोगों को भयमुक्त जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ताइवान के लोगों के लिए अधिकारवाद से लोकतंत्र की ओर का मार्ग एकतरफा है और हम इस पर आगे बढ़ते रहेंगे।

ताइवान को 'चीन का हिस्सा' बताते हुए चीन सरकार कई बार खुल्लमखुल्ला तौर पर यह धमकी दे चुकी है कि वह ताइवान को वापस चीन में मिलाने के लिए सैनिक हमले का रास्ता भी खुला रखे हुए है। कई रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि बीजिंग ओलंपिक के बाद चीन यह कदम उठा सकता है।

यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष एडवर्ड मेकमिलन स्काट ने तिब्बत और बौद्धों सहित धार्मिक तथा

जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता जताई।

जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय, भारत के एक प्रोफेसर फुंसोक स्तोब्दान ने तिब्बती तुलकू (अवतारी) लामाओं के चयन में चीन सरकार के बढ़ते दखल का जिक्र किया और इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह दखल चिंताजनक है। ह्यूमन राइट्स विदाउट बोर्डर्स के अध्यक्ष विली फाउटर ने दलाई लामा के विशेष दूत लोडी ग्यालतसेन ग्यारी का उद्धरण देते हुए कहा, ''लामाओं के अवतार की प्रणाली तिब्बत की धार्मिक परंपराओं का एक प्रमुख विश्वास है। इसलिए अपने प्रत्याशी को जबरन थोपना इस विश्वास व्यवस्था के उल्लंघन से कम नहीं है।''

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक पूर्व एशियाई अध्ययन प्रोफेसर रास टेरिल ने गैर–चीनी क्षेत्रों पर चीन के अधिकार को 'अर्ध उपनिवेशी शासन' करार दिया। संगोष्ठी के प्रतिभागियों ने तिब्बत मामले के संभावित समाधानों पर भी चर्चा की।

विद्वान जेम्स सेमुअर ने सुझाव दिया कि हांगकांग–माडल : 'एक देश, दो प्रणालियां ' एक विकल्प हो सकता है।

बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार का आह्वान

संगोष्ठी के आखिर में एक वक्तव्य जारी किया गया जिसमें दुनिया भर के राजनेताओं से आह्वान किया गया है कि अगर चीन मानवाधिकार संबंधी अपने रिकार्ड को सुधाने में विफल रहता है तो वे बीजिंग–2008 ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं हों।

वक्तव्य में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी से भी बीजिंग ओलंपिक को स्थगित करने पर गंभीरता से विचार करने को कहा गया है क्योंकि चीन ने मानवाधिकार संबंधी अपने रिकार्ड में सुधार के लिए अभी तक बहुत मामूली कदम उठाये हैं।

इसमें चीन की सरकार से आग्रह किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बीजिंग ओलंपिक की कवरेज मुक्त ढंग से करने की अनुमति दे। इसके अलावा 11 श्रेणियों के लोगों पर आयोजन में भाग लेने पर प्रतिबंध को भी समाप्त करने को कहा गया है।

दलाई लामा, निर्वासित तिब्बती सरकार तथा तिब्बत में स्वशासन का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर खेलों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध को तत्काल समाप्त करने की मांग इस वक्तव्य में की गई है। वक्तव्य में चीन की धार्मिक स्वतंत्रता के वैष्विक मूल्य का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की गई है।

चीन सरकार तिब्बत के धार्मिक मामलों में दखल बंद करे

भारत–तिब्बत संसदीय मंच के संयोजक श्री बशिष्ठ नारायण सिंह की चीनी राष्ट्रपति से मांग

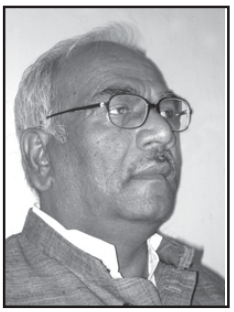

भारत–तिब्बत सर्वदलीय संसदीय मंच के संयोजक और सांसद श्री बशिष्ठ नारायण सिंह ने चीनी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर तिब्बती धर्मगुरुओं के पुनर्अवतार के बारे में नए चीनी आदेश की आलोचना की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उपरोक्त पत्र को ***'तिब्बत देश'*** के पाठकों के लिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा है:

20 सिबंबर, 2007

श्री हू जिंताओ,
राष्ट्रपति, चीन गणराज्य

महामहिम जी,

हमें यह जानकर गहरी निराशा हुई है कि चीन के धार्मिक शासकीय विभाग ने 'आर्डर नबंर 5' दस्तावेज़ जारी किया है जिसमें तिब्बत के 'लिविंग बुद्धों' (अवतारी लामाओ) के पुनर्अवतार के बारे में 14 नए नियम घोषित किए गए हैं। इन नियमों को 1 सितंबर से लागू किए जाने की घोषणा की गई है। तिब्बती जनता के धार्मिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन करने वाले इस आदेश की हम कड़ी निंदा करते हैं।

हम रोंग्ये आद्राक और कुछ अन्य तिब्बती नागरिकों के भविष्य के बारे में भी चिंता व्यक्त करते हैं जिन्हें हाल ही में चीन सरकार द्वारा तिब्बत में किए जा रहे गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण गिरफ्तार किया गया है। हम आपसे अपील करते हैं कि इन्हें और ऐसे सभी तिब्बती नागरिकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाए जो अपने विचार व्यक्त करने के मूलभूत अधिकार के राजनीतिक कारणों से कैद में रखे गए हैं।

हम चीन गणराज्य की सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह तिब्बत में चल रहे दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोके और इन्हें ठीक करने के समुचित कदम उठाए।

आदर सहित

बशिष्ठ नारायण सिंह, संयोजक एपीआइपीएफटी

तिब्बती जनता के धार्मिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन करने वाले इस आदेश की हम कड़ी निंदा करते हैं। हम चीन गणराज्य की सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह तिब्बत में चल रहे दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोके और इन्हें ठीक करने के समुचित कदम उठाए।

दलाई लामा ने बर्मा में लोकतंत्र आंदोलन का समर्थन किया

सैनिक शासकों से करुणा और शांति की अपील

धर्मशाला, 24 सितंबर दलाई लामा ने बर्मा में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाए जा रहे आंदोलन की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।

23 सितंबर को अपने जारी अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ''बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हाल ही में चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। मैं उनकी ओर से स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए किए जा रहे आहवान का पूरी तरह समर्थन करते हुए विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करता हूं कि वे इस तरह के अहिंसक आंदोलन को अपना सहयोग दें।''

''बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हाल ही में चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। मैं उनकी ओर से स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए किए जा रहे आहवान का पूरी तरह समर्थन करते हुए विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करता हूं कि वे इस तरह के अहिंसक आंदोलन को अपना सहयोग दें।''

अपने इस बयान में उन्होंने कहा, ''एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते मैं वहां के सैनिक शासन के उन लोगों से अपील करता हूं जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं कि वे इस मामले में धर्म में निहित करुणा और अहिंसा के नियमों का पालन करें।''

इस आंदोलन की सफलता की कामना करते हुए दलाई लामा जी ने इस संदेश में आगे कहा है कि, ''मैं इस शांतिपूर्ण आंदोलन की सफलता और अपनी साथी नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची की रिहाई के लिए प्रार्थना करता हूं।''

जापानी प्रधानमंत्री के सुझावों पर चीन में तीखी प्रतिक्रिया

बीजिंग भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान को लेकर वृहद एशियाई भागीदारी के संबंध में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा नई दिल्ली में दिए गए सुझाव की चीन के सरकारी विद्वानों ने कड़ी आलोचना की है। भारत में भी यह महसूस किया जा रहा है कि चीन खतरे से निबटने के लिए जापान, वियतनाम और द.कोरिया जैसे उन देशों से सहयोग बढ़ाना चाहिए जो चीनी दादागीरी से परेशान हैं।

चीन ने दावा किया है कि यह शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है और यह क्षेत्रीय शांति के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय संसद में व्यापक विदेश नीति पर भाषण देते हुए जापानी प्रधानमंत्री आबे ने व्यापक एशियाई भागीदारी का विचार रखा जिसमें जापान के अतिरिक्त भारत, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात कही गई थी। इस भाषण में चीन का उल्लेख नहीं किया गया था।

चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि जापान, भारत, अमेरिका और आस्ट्रेलिया को मिलाकर लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाने पर आबे का विचार क्षेत्रीय स्थिरता तथा शांति की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। यह एशिया को विचारधारा के आधार पर बांट सकता है।

चाइना डेली के अनुसार चाइना इंस्टीट्यूट आफ कंटेपररी इंटरनेशनल रिलेशन के एक विशेषज्ञ हू शिशेंग ने कहा है कि चतुर्पक्षीय गठबंधन का विचार शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है। और जानबूझकर एशिया को बांटने के लिए इसका खाका तैयार किया गया है। हू ने कहा कि जापान की मंशा साफ है। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव की काट तैयार करना है। चीन के सामाजिक विज्ञान अकादमी में एशिया प्रशांत अध्ययन संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर सुन शिआई ने भी हू के विचारों से सहमति जताई और कहा कि तथाकथित लोकतांत्रिक गठबंधन एशिया के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन पर अंकुश लगाने का कोई भी प्रयास काम नहीं करेगा।

अपने भाषण में आबे ने भारतीय सांसदों से कहा था कि यह भागीदारी एक संघ है जिसमें हम साझाा बुनियादी मूल्य यथा स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मूलभूत मानवाधिकार के साथ साथ सामरिक हित रखते हैं।

दलाई लामा ने बार्सेलोना में तिब्बत हाउस फाउंडेशन का उद्घाटन किया

बार्सेलोना परमपावन दलाई लामा ने बार्सेलोना में नये टिबेट हाउस फाउंडेशन का उद्घाटन 11 सितंबर को किया। उन्होंने भवन के मुख्य द्वार पर रिबन काटा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तिब्बती तथा अन्य समर्थक मौजूद थे।

परम पावन दलाई लामा ने बाद में सेरा तथा अन्य विहारों के भिक्षुओं के साथ प्रार्थना की। उन्होंने तिब्बत हाउस फाउंडेशन के सदस्यों और प्रायोजकों से इसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने टिबेटन कम्युनिटी आफ स्पेन के सदस्यों से भी बातचीत की। दलाई लामा ने कहा कि इस हाउस का इस्तेमाल अकादमिक केंद्र के रूप में किया जाना चाहिए जहां इस क्षेत्र के लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान सकें और आपस में चर्चा कर सकें। दलाई लामा ने इसी दिन बार्सेलोना के आर्कबिशप से भी मुलाकात की। दोनों हस्तियों ने आध्यात्म से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया।